

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-88 / 2008

बुंदू खान

—अपीलार्थी

बनाम

1. अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु।
3. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित -

अपीलार्थी की ओर से : श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान संशोधित कर इसके पश्चात अधिक वेतन की वसुली जमा कराने बाबत दिये गये पत्र दिनांक 09.01.2008 को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.12.1966 को हुई थी एवं उसी तारिख से गणना करके अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति से गणना नहीं की जाकर बाद की तिथि से गणना की जा रही है, जो गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलौच्य आदेश दिनांक 09.01.2008 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना है कि 18 एवं 27 वर्ष का चयनित वेतनमान जो दिनांक 25.01.1994 एवं दिनांक 17.05.1998 को स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए 18 वर्ष का चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1994 के स्थान पर दिनांक 25.01.1992 से एवं 27 वर्ष का चयनित वेतनमान दिनांक 17.05.1998 के स्थान पर दिनांक 17.05.2000 किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी. बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का

अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing

ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

4. अतः बिन्दू संख्या-1 व 4 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण तिथि से कार्मिक की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है और उसी तिथि से गणना पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रश्न संख्या-सी में यह भी माना गया है, जहां पूर्व में 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रदान किया जा चुका है, वहां पर कार्मिक से वसुली नहीं की जावे। प्रकरण में अपीलार्थी को लाभ दिये जाने के पश्चात अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को देखते हुए उचित नहीं है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :-

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
- (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
- (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
- (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
- (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

5. उपरोक्त निर्णय में यह माना है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात वसुली किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकरण में अपीलार्थी दिनांक 01.02.2003 को

स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुका है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, उसे संशोधित नहीं किया जावे एवं अपीलार्थी से कोई वसुली नहीं की जावे। पूर्व में प्रदान किये गये चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को देय होगा। अतः पूर्व में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के बाद कोई वसुली की गई है तो वसुल की गई राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)